प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं हो सकता कि वह दूसरों पर बिना उनकी मर्जी के राज कर सके। - अब्राहम लिंकन

नेपाली विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एक बड़ा महत्व तो यही है कि नेपाल द्वारा अपने नक्शे में किए गए विवादास्पद बदलाव से उपजी तल्खी के बाद यह किसी वरिष्ठ नेपाली नेता की पहली भारत यात्रा थी। हकीकत यह भी है कि नेपाल उन देशों में है, जिन्हें भारत सबसे पहले वैक्सीन देना चाहता है।

भरोसे पर टिका रिश्ता

भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक के सिलसिले में नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली की हाल ही में संपन्न यात्रा नेपाल द्वारा अपने नक्शे में किए गए विवादास्पद बदलाव की वजह से दोनों देशों में आई तल्खी ही नहीं, बल्कि महामारी के बाद इस पड़ोसी देश के किसी वरिष्ठ नेता की पहली यात्रा की वजह से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ध्यान रहे, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ओ पी शर्मा ओली की सिफारिश पर वहां की संसद भंग कर दी गई है और वहां कार्यवाहक सरकार काम कर रही है। निश्चय ही किसी भी अन्य देश की तरह नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत हस्तक्षेप नहीं करता, मगर ओली सरकार ने जिस तरह से नेपाल के नक्शे में बदलाव लाकर भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपने नक्शे का हिस्सा बनाया, उसने स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली को नाराज कर दिया। ज्ञवाली और विदेश मंत्री एस जयंशकर के बीच, हालांकि इस मसले पर बात नहीं हुई है, लेकिन भारत की स्थिति साफ है कि वह अपनी संप्रभुता से किसी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं कर सकता। भारत और नेपाल की 1,800 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसके अधिकांश हिस्से को द्विपक्षीय सहमति से सुलझाया जा चुका है। ज्ञवाली ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि बचे हिस्से में सीमा का स्वीकार्य समाधान तलाशने से सकारात्मक संदेश जाएगा और द्विपक्षीय संबंधों में भरोसा बढ़ेगा। भारतीय पक्ष ने उनकी यात्रा को संयुक्त आयोग से जुड़े मसलों तक सीमित रखकर स्पष्ट कर दिया कि सीमा संबंधी मसलों पर बातचीत का मंच अलग है। बेशक, नेपाल में चीन की दखलंदाजी के कारण भारत से उसके रिश्ते पर फर्क पड़ता है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने इस पुराने मित्र के प्रति सद्भावना दिखाई है। नक्शे में बदलाव की वजह से आई तल्खी के बावजूद हाल के दिनों में भारतीय विदेश सचिव और भारतीय सेनाध्यक्ष ने नेपाल की यात्रा की थी। यही नहीं, भारत ने पहले ही स्पष्ट किया था कि महामारी की वैक्सीन जब भी आएगी, वह नेपाल तथा अन्य जरूरतमंद देशों को इसकी आपूर्ति करेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है और महामारी के समय भारत की ओर से दिखाई गई सद्भावना ने इसे मजबूत ही किया है।

विश्व मंच पर दमदार मौजूदगी का अवसर

विदेश नीति के मोर्चे पर नया साल भारत को वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष जहां सभी देश अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने को शीर्ष प्राथमिकता में रखेंगे, वहीं भारत को इसके अलावा पड़ोसी देशों से संबंध भी सामान्य बनाने होंगे।

के. एस. तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति को वर्ष 2021 में तेजी से लागू करने की जरूरत है, क्योंकि इस मोर्चे पर विफलता चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जबकि इस मामले में हमारा अभिनव दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दे सकता है, जिससे दक्षिण एशियाई देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और भरोसा प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भारत कोविड-19 और चीन की आक्रामकता से जूझ रहा था, जिसका खास तौर से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, जबकि नए वर्ष में भारत ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, पश्चिम एशियाई देशों और अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने की चुनौतियों के साथ प्रवेश किया है।

नया साल भारत को आकांक्षी खिलाड़ी के बजाय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करता है, पर यह चीन द्वारा गुमराह और लुभाए गए पड़ोसियों का भरोसा जीतने के लिए नीतिगत बदलावों पर निर्भर करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि नए रणनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका, यूरोपीय संघ, मुस्लिम देशों आदि में नए शासन से निपटने के लिए अधिक से अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत का उदय आक्रामक और शत्रुतापूर्ण चीन की छाया में हो रहा है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की मुखरता को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह भारत के निकट पड़ोसी देशों में हावी होना चाहता है।

पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित कर मोदी सरकार को दिखाना होगा कि भारत में क्षेत्रीय शांति और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने की क्षमता है। भारत को यूरोप को लुभाने तथा ब्रिटेन के साथ बातचीत से पहले ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के सौदे पर नजर रखने की आवश्यकता है। आगामी मई में भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन होने की संभावना है। फ्रांस और जर्मनी अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ सामने आए हैं,

लेकिन भारत के वार्ताकारों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ-चीन के व्यापार समझौते को खारिज कर दिया। भारत को अपने पड़ोस में चीन की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की मदद मांगने की नीति का दोहन किया है, जिससे भारत के खिलाफ इस दुष्ट राष्ट्र का इस्तेमाल करने की आशंका बढ़ जाती है।

भारत को नए साल में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडन से बड़ी उम्मीदें हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के अलावा चीन पर नियंत्रण रखने के लिए भारत के मजबूत संबंधों पर जोर दिया है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि बड़ी योजनाओं में अमेरिका चीन को किस तरह देखता है। भारत, अमेरिका-चीन व्यापार समझौते के निहितार्थों को बारीकी से देखेगा और उन प्रमुख परीक्षणों में क्वाड का भविष्य तथा नए अमेरिकी प्रशासन की हिंद प्रशांत रणनीति होगी। नई दिल्ली को अमेरिका के साथ अपने गहन रणनीतिक और रक्षा संबंधों को बढ़ाना चाहिए और व्यापार और वीजा मुद्दों को हल करने का विकल्प चुनना चाहिए।

भारत को जम्मू-कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, जिसे चीन प्रोत्साहित करता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर सख्ती से इसका जवाब दिया था, लेकिन असंख्य संघर्ष विराम उल्लंखन जारी हैं। बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान पर चीन का 19 अरब डॉलर बकाया है। चीन के कर्ज का बढ़ता बोझ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जुआ है, इसलिए संबंधों में सुधार की संभावना दूर की कौड़ी है।

इधर नेपाल भारत के लिए नया सिरदर्द बना है। इस साल प्रधानमंत्री ओली की विदाई से संबंधों के आयाम खुल सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने पहले ही पहल करते हुए ओली सरकार से बातचीत करने के लिए विदेश सचिव और सेना प्रमुख को भेजा था। भारत को नेपाल में चुनाव के बाद नई सरकार से बातचीत को पुनर्जीवित करना होगा, जो उम्मीद है कि चीन की कठपुतली नहीं होगी।

भारत को अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी अपने संबंध सुधारने चाहिए। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेश ने बेरुखी दिखाई थी, जो भारत का आंतरिक मामला था। नतीजतन भारत ने सीएए के नियमों को अधिसूचित नहीं किया। ऐसा लगता है कि भारत मालदीव में अमेरिका की भागीदारी से शांति स्थापित कर रहा है और खुद को जापान के साथ जोड़ रहा है, जिसके श्रीलंका और मालदीव में काफी कुछ दांव पर है, इसलिए इन प्रयासों को जारी रखना चाहिए।

भारत की 'आत्मनिर्भरता' की सार्वजनिक अभिव्यक्ति और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने को व्यापक रूप से 'अलगाववादी' और 'स्वार्थी ' के रूप में देखा गया। इसलिए नए साल में इस पर सख्त नजर रखने की जरूरत है, ताकि चीन के वर्चस्व पर अंकुश लगाने के अलावा अर्थव्यवस्था की गिरावट को रोकने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकें। चूंकि सीमा पार आतंकवाद भारत की प्रमुख चिंताओं में से एक है, इसलिए भारत पाकिस्तान को आगे भी अलग-थलग रखने के लिए काम करेगा, जबकि पाकिस्तान भारत को वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा से विचलित करेगा।

जहां तक ईरान के साथ भावी संबंधों की बात है, तो बाइडन प्रशासन ओबामा शासन के दौरान मौजूद अमेरिका-ईरान संबंधों के मूल रवैये का पालन कर सकता है। अब भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों को आसान बनाने के लिए सख्त रुख अपनाने और योगदान देने की जरूरत है, जिसका हमारे लिए काफी रणनीतिक महत्व होगा। ईरान हमारा विश्वसनीय दोस्त है, जो अतीत में पाकिस्तान की शरारती चालों के खिलाफ खड़ा रहा है। हालांकि सभी देशों को नए साल में अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने को शीर्ष प्राथमिकता में रखना होगा, लेकिन भारत को इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी सामान्य बनाना होगा।

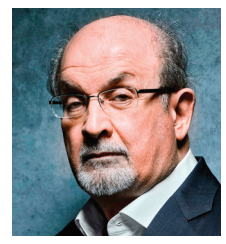

सलमान रुश्दी
ब्रिटिश भारतीय लेखक

मुखड़ा क्या देखे दर्पण में

जब तक हवा सांस लेने लायक है, तब तक यह हमारे लिए मुद्दा नहीं बनती। हां, अगर किसी दिन हवा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो, तो आवाज जरूर उठेगी।

लेखक की स्वतंत्रता हवा की तरह है

कोई भी लेखक कभी सेंसरशिप पर बात नहीं करना चाहता। लेखक सिर्फ रचना पर बात करना चाहता है, जबकि सेंसरशिप रचना-विरोधी है, नकारात्मक ऊर्जा है। सेंसरशिप ऐसी चीज है, जो आपको वह काम करने से रोक देती है, जो आप करना चाहते हैं। जबकि लेखक सिर्फ उस पर बात करना चाहते हैं, जिस पर वे काम कर रहे हैं। वे उस पर बात नहीं करते, जिससे उन्हें रोका गया है। लेखक इस पर बात करना चाहते हैं कि उन्हें अपनी किताब के लिए कितने पैसे मिले। लेखक अपने प्रकाशकों और आलोचकों की आलोचना करना चाहते हैं और राजनेताओं को जकड़े रहना चाहते हैं। लेखक इस पर बात करना चाहते हैं कि उन्हें किन चीजों से प्यार है, उन्हें कौन-से लेखक पसंद हैं, कौन-सी कहानियों और वाक्यों का उनके लिए खास अर्थ और महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वे अपने विचारों और अपनी कहानियों पर बात करना चाहते हैं। ब्रिटिश हास्य लेखक पॉल जेनिंग्स ने प्रतिरोधात्मकता पर अपने अद्भुत लेख में लिखा है कि यह दुनिया दो श्रेणियों में विभाजित है-वस्तु और गैर वस्तु तथा इन दोनों में कभी खत्म न होने वाली लड़ाई चलती रहती है। अगर लिखना वस्तु है, तो सेंसरशिप गैर वस्तु है, और जैसा कि किंग लियर ने कॉर्डेलिया से कहा था, कुछ नहीं से कुछ नहीं ही निकलेगा, या जैसा कि जेनिंग्स ने शेक्सपीयर को संशोधित करते हुए लिखा कि किसी गैर वस्तु से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हवा का ही उदाहरण लें। यह कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो, हमें सांस लेने के लिए मुफ्त हवा इफरात में मिल रही है। इसलिए यह मांग करना फिजूल है कि लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा उपलब्ध कराई जाए। हां, अगर किसी दिन हवा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो, तो आवाज जरूर उठेगी।

अगर कलाकार को आगामी कल की स्वतंत्रता के बारे में संदेह है, तो फिर वह आज भी स्वतंत्रता का एहसास नहीं कर पाएगा। अगर हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, तो भय में जी रहे हैं।

स्वतंत्रता हवा की तरह है, जो पर्याप्त भी है और इफरात भी। जब तक हवा सांस लेने लायक है, तब तक यह हमारे लिए मुद्दा नहीं बनती। तब तक हम हवा की उपलब्धता को बहुत सहज और उदासीन भाव से लेते हैं। और रात को सोते हुए ऐसा मान लेते हैं कि आज दिन भर हम जिस तरह स्वतंत्र थे, कल भी उसी तरह स्वतंत्र रहेंगे। रचनात्मक कला के लिए न केवल स्वतंत्रता जरूरी है, बल्कि स्वतंत्रता की भावना भी बहुत आवश्यक है। अगर कलाकार को आगामी कल की स्वतंत्रता के बारे में संदेह है, तो वह आज भी स्वतंत्रता का एहसास नहीं कर पाएगा। अगर वह अपनी किसी रचना का राजनीतिक खामियाजा भुगतने के बारे में सोचकर भयभीत है, तो उसकी रचना के चयन का आधार उसकी प्रतिभा नहीं, बल्कि भय होगा। अगर हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, तो भय में जी रहे हैं। सबसे बदतर स्थिति तो तब होती है, जब कला पर सेंसरशिप का हमला होता है। तब कला सेंसर्ड कला बन जाती है। फिर दुनिया भी उस कला को उसी दृष्टि से देखने लगती है। सेंसरशिप किसी कला को अनैतिक, ईशनिंदात्मक, अश्लील या विवादास्पद बना देती है। फिर उस कला की स्वतंत्र पहचान नहीं रह जाती। तब जुर्म की मानसिकता रचनात्मक निर्दोषिता की भावना पर हावी हो जाती है और नैतिक सवाल उठने लगते हैं। उस रूसी लेखक ने अपने नायक को एक वेश्या से प्रेम करते क्यों दिखाया, क्या कोई सुशील नायिका नहीं थी? उस ब्रिटिश नाटककार को ऐसी जगह पर यौन हिंसा के दृश्य क्यों रखने चाहिए थे, जिससे किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचती है? चीन अपने ज्यादातर नागरिकों में यह भावना पैदा करने में सफल हुआ है कि तियानमेन चौक पर हिंसा करने वाले नायक नहीं, खलनायक थे। यह सेंसरशिप की सच्ची विजय है।

गोपीनाथ आर

मंजिलें और भी हैं

मैं नहीं चाहता था कि मैंने शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वही उन बच्चों को भी करना पड़े। इसलिए मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। 2009 से अब तक इस स्कूल से सैकड़ों बच्चे शिक्षित होकर निकल चुके हैं।

मजदूरों के बच्चों की शिक्षा से संवर रही है जिंदगी

मैं कर्नाटक के कोलार जिले के एक गांव से ताल्लुक रखता हूं। बचपन में ही मेरे पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया। वह बंगलूरू चले गए। अपना जीवन चलाने के लिए मुझे अपने भाई-बहन व मां के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। प्रत्येक दिन स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता, तो सोचता कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूं। कुछ वर्ष बाद मेरे पिता वापस आए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। फिर वह मुझे बंगलूरू ले गए। वहां मेरी सौतेली मां ने एक स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया, लेकिन मुझे स्कूल के बाद घंटों पिता के साथ काम करना पड़ता था। सामाजिक क्षेत्र में परास्नातक के बाद मैंने कई संगठनों के साथ काम किया। बंगलूरू में जब मैं सड़क पर घूमते, या बिल्डिंगों के लिए काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को देखता, तो मुझे अपना संघर्ष याद आता था। इसलिए मैंने ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जिसमें पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ वे रचनात्मक शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं।

शिक्षा ही समाधान

भीख मांगने वाले और मजदूरों के बच्चों से बात करके मैंने महसूस कि मैं जिस स्थिति से बचपन में गुजरा हूं, वे भी उसी से गुजर रहे थे। मुझे लगा कि शिक्षा ही इसका समाधान बन सकती है। हमारे कुछ प्रयासों के बाद माता-पिता भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए।

आश्रय, भोजन व शिक्षा

मैंने प्रत्येक दिन शाम को एक जगह पर बच्चों को पढ़ाना और उन्हें व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मेरे कुछ दोस्त भी इस काम में मदद करने लगे और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद मैंने एक स्थायी स्कूल बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया और एक आवासीय स्कूल का निर्माण किया। इसमें तकरीबन 300 बच्चे रहते हैं। उन्हें मुफ्त में आश्रय व भोजन के साथ शिक्षा मिल रही है।

आगे बढ़ते बच्चे

चूंकि यहां पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे, गरीब, मजदूर, खदानों में काम करने वाले लोगों के हैं। साथ कई बाल-मजदूरी के चंगुल से छुड़ाए गए हैं। इसलिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कई कॉरपोरेट कंपनियां हमारा आर्थिक सहयोग करती हैं। हमारे स्कूल से निकलकर कई बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं। उनमें से कई नौकरी करने लगे हैं, साथ ही उच्च शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं।

(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

आंकड़े

बैंक एटीएम

नकद निकासी सुविधा को आसान बनाने के लिए पूरे देश में बैंकों ने विभिन्न जगहों पर एटीएम स्थापित किए हैं। 31 मार्च 2020 तक इस क्षेत्र में एसबीआई शीर्ष पर है।

देश में सर्वाधिक एटीएम एसबीआई के हैं

एसबीआई	एक्सिस बैंक	आईसीआईसीआई बैंक	एचडीएफसी बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	पीएनबी
58,555	17,477	17,430	14,061	13,193	9,168

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

महिला संत ने कहा, तुम दोनों न लड़ने का संकल्प लो और प्रेम से रहना सीखो, मैं तभी भोजन करूंगी। गालियां देने वाले का भोजन मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा।

महिला संत की प्रेरणा

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

दक्षिण भारत की महिला संत औव्वैयार बचपन में ही अनाथ हो गई थीं। एक सद्गृहस्थ संत ने, जो प्रभु भक्ति के गीत रचते थे, उनका पालन पोषण किया। अपने धर्मपिता के भक्ति गीतों ने औव्वैयार को भगवत् भक्ति की प्रेरणा दी। दस वर्ष की आयु होते ही वह भी भक्ति गीतों की रचना करने लगीं। अपने इष्ट देवता विघ्नेश्वर की पूजा-उपासना में लीन रहतीं। कठोर तप और साधना के बल पर उन्हें अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई। बीमार और दुखी उनके पास पहुंचते, तो वह उन्हें जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधि देतीं और भगवान का भजन करने और सात्विक जीवन जीकर निरोगी बनने की प्रेरणा देतीं। वह स्वयं गांवों और नगरों का भ्रमण कर लोगों को सदाचार का उपदेश देतीं। एक बार वह किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचीं। उन्होंने देखा कि पति-पत्नी किसी बात पर झगड़ते हुए एक-दूसरे को कटु वचन कह रहे हैं। यह देखकर वह वापस लौटने लगीं। गृहस्वामी उन्हें पहचान गया और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, तुम दोनों भविष्य में न लड़ने का संकल्प लो और प्रेम से रहना सीखो, मैं तभी भोजन करूंगी। क्रोध में आकर गालियां देने वाले का भोजन मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसके बाद पति-पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर क्रोध त्यागने का संकल्प लिया।

-अमर उजाला आर्काइव से।

शिलालेख

मैं फिर कहता हूं
धर्म नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा -
मगर मेरी/ कोई नहीं सुनता!
हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं -
जो सुनते हैं
बहरे हैं या
अनसुनी करने के लिए
नियुक्त किए गए हैं

- श्रीकांत वर्मा

भारत के ऊर्जा क्षेत्र का विरोधाभास

भारत को जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों को कम करने के लिए कोयला के उपयोग को खत्म करने की आवश्यकता है।

ब्रतोती राय

जलवायु परिवर्तन

हाल के शोध से पता चलता है कि 75 प्रतिशत भारतीय जिले चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में हैं। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में भारत का प्रदर्शन बताता है कि वह जलवायु परिवर्तन के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ है। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-2015 के दौरान, भारत सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से लगभग 40 प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने का संकल्प लिया। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता की बातचीत के बावजूद भारत में कोयला का उपयोग बढ़ रहा है और भारत इस प्रकार के ऊर्जा उपयोग से दूर जाने के बजाय जीवाश्म ऊर्जा वाहक के साथ अपने संबंधों को गहरा करने की प्रक्रिया में है। भारत अब 2023-24 तक सालाना एक अरब टन कोयला निकालने की राह पर है। पहले से ही निजी कंपनियों को कोयला खनन के लिए

41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की गई है, जिसमें जनजातीय समुदायों द्वारा लगाए गए प्राचीन जंगल और समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र शामिल हैं। यह नई कोयला खदानों के लिए अगले 55 ब्लॉकों की नीलामी करने और अगले पांच वर्षों में कम से कम 193 वर्तमान खानों का विस्तार करने की योजना के अतिरिक्त है। तर्क दिया जाता है कि आर्थिक विकास और रोजगार के लिए उद्योगों एवं सेवाओं का विस्तार, बिजली तक पहुंच में सुधार और ऊर्जा के मामलों में गरीबों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन जैसे विकास कार्यों के लिए कोयले की जरूरत है। हालांकि भारत की बिजली का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता उद्योग है, जो लगभग 40 प्रतिशत बिजली की खपत करता है, जबकि घरों के लिए यह आंकड़ा 25 प्रतिशत से कम है, घरेलू खपत में भारी असमानता है।

कोयले की पूरी आपूर्ति श्रृंखला के कारण भारी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत चुकानी होती है। समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्पादित कोयला पर्यावरणीय संकट पैदा करता है और स्वाभाविक रूप से भूमि की बेदखली, आजीविका के विनियोग, और जल और वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के आसपास रहने वाली आबादी में समय से पहले मृत्यु दर 80,000 से 1,15,000 प्रति वर्ष होती है। कोयला खदानों के आसपास के लोगों और उसमें काम करने वाले श्रमिकों को कई तरह बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख है फेफड़ा काला होने की बीमारी और प्रदूषित जल जनित बीमारी।

नतीजतन कोयला देश भर में विरोध और संघर्ष का विषय बन गया है। ये संघर्ष भारत में व्यापक पर्यावरण न्याय आंदोलन का एक हिस्सा हैं, जो लोगों और पृथ्वी की चिंताओं का निपटारा किए बिना देश के विकास के समक्ष स्वायत्तता और सामाजिक-पारिस्थितिक कल्याण का दावा करते हैं। कोयले के खिलाफ इनमें से कई विरोध दशकों से चल रहे हैं। ऐसा ही एक संघर्ष झारखंड के हजारीबाग जिले में 2004 से ही चल रहा है, क्योंकि न केवल जैव विविधता वाले जंगलों और कृषि भूमि पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, बल्कि इस क्षेत्र में खोजे गए प्रागैतिहासिक महापाषाण काल पर भी। कोविड-19 संकट के बीच भी असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में कोयला खनन को रोकने के लिए ऑनलाइन आंदोलन देखा गया। भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति सच्चे बने रहने और देश में जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को खत्म करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस चरण में दो चीजों को शामिल करना होगा जो भारत सरकार की वर्तमान योजना से गायब हैं। सबसे पहले, सरकार को 'खदान में कोयले' को छोड़ देना चाहिए, भले ही यह अब भी 'आर्थिक रूप से व्यवहार्य' माना जाता है, तब भी इसके खनन को रोकना चाहिए। दूसरा, लोगों, सरकार और व्यवसायियों के एक जबर्दस्त संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है कि ऊर्जा प्रणाली को न केवल जीवाश्म ईंधन और नाभिकीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, बल्कि एक भारी पूंजीकृत, केंद्रीकृत प्रणाली से स्थानीय रूप से नियंत्रित एक विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रावधान की तरफ बढ़ा जाए।

-लेखिका बर्सिलोना के स्वायत्त विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में एन्वाजस्टिस टीम का हिस्सा हैं।